भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3699

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट को रोकना

3699. श्री करण भूषण सिंहः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गोंडा और बहराइच में खेती में अत्यधिक रसायनों के उपयोग से मिट्टी खराब हो गई है और कृषि विज्ञान केंद्रों के आकलन में दालों, तिलहनों और अनाजों की पैदावार को प्रभावित करने वाली सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को चिह्नित किया गया है;

(ख) क्या ये जिले प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) के अंतर्गत शामिल हैं और यदि हाँ, तो नवंबर 2024 से प्रत्येक जिले में बनाए गए संकुल, नामांकित किसानों और जैव-आदान संसाधन केंद्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जिलों में अब तक कितनी राशि जारी की गई है और कितने किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक एनएमएनएफ़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है; और

(घ) उक्त जिलों के प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए पीजीएस-इंडिया प्रमाणन और बाजार तक पहुंच का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रिपोर्ट किया है कि कृषि विभाग, गोंडा और कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के माध्यम से मृदा उर्वरता का आकलन किया है। यह आकलन कृषि योग्य मृदा के एक हिस्से में सल्फर और जस्ता की कमी दर्शाते हैं। इससे दलहन, तिलहन और अनाज की फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। तथापि, मृदा परीक्षण के परिणामों से संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने के कारण सल्फर की मात्रा में सुधार के संकेत मिले हैं। कृषि विभाग और केवीके किसानों को जागरूक करने, प्रशिक्षण देने और प्रदर्शन करने के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड-आधारित उर्वरक अनुशंसाओं, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और सल्फर एवं जस्ता उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

(ख): उत्तर प्रदेश राज्य की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 में बहराइच जिले में 15,000 किसानों को शामिल करते हुए 120 क्लस्टर बनाए गए और 2 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित किए गए। गोंडा जिले में 1,250 किसानों को नामांकित करते हुए 10 क्लस्टर बनाए गए और 2 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित किए गए।

(ग): उत्तर प्रदेश राज्य की वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार, एनएमएनएफ के तहत बहराइच जिले को 1,347.96 लाख रुपए जारी किए गए और 15,000 किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ का वार्षिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, मिशन के तहत गोंडा जिले को 117.89 लाख रुपए जारी किए गए और 1,182 किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ का वार्षिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

(घ): मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए प्राकृतिक कृषि प्रमाणन प्रणाली (एनएफएस) आरंभ की गई है। एनएफएस सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया नेचुरल) के तहत डिजिटल ऑनलाइन प्रमाणन को अपनाता है, जिसका लोगो "पीजीएस-इंडिया नेचुरल" है। अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में 24.7 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रणाली (एनएफएस) के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं और 23.0 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्राकृतिक खेती प्रमाणित उत्पाद बाजार में और साथ ही ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर बिजनेस टू कंज्यूमर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

******